

पटना में दिनांक-14 अक्टूबर, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. बांका जिलान्तर्गत बाराहाट अंचल के मौजा- खड़हरा एवं मौजा-लहौरिया के कुल 2.71 एकड़ भूमि (विवरणी संलग्न-अनु०-1) 11,14,800/- (ग्यारह लाख चौदह हजार आठ सौ) रूपया सलामी एवं सलामी के 5% का 25 गुणा अर्थात् 13,93,500/- (तेरह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ) रूपया पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 25,08,300/- (पच्चीस लाख आठ हजार तीन सौ) रूपये के भुगतान पर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० को पावर ग्रिड की स्थापना हेतु स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2. पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी अंचल के मौजा-रामपुर फरसाही, थाना नं०-15, खाता सं०-1534, खेसरा सं०-375, रकबा-0.50 एकड़ जल संसाधन विभाग के लिए पूर्व अर्जित भूमि को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 50,00,000/- (पचास लाख) रूपए भूमि के बाजार मूल्य के समतुल्य सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत के 25 गुणा अर्थात् 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रूपए पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 75,00,000/- (पचहत्तर लाख) रूपए के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को स्थायी हस्तान्तरण।

2. स्वीकृत।

वित्त विभाग

3. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2014 के प्रभाव से 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

वित्त विभाग

4. अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक-01.07.2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

4. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रस्तावित भवन निर्माण योजना हेतु कुल रूपये 8,00,00,000/- (आठ करोड़) रूपये मात्र एवं कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु कुल रूपये 2,00,00,000/- (दो करोड़) मात्र अर्थात् कुल रूपये 10,00,00,000/- (दस करोड़) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
5. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

6. बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के गठन के फलस्वरूप आयोग को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु आयोग में अध्यक्ष, सदस्यों एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 88 पदों के सृजन एवं इनके सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 3,96,39,200/- (तीन करोड़, छियानबे लाख, उनचालीस हजार, दो सौ) की स्वीकृति के संबंध में।
6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. श्री राम गुलाम (बि०प्र०से०, सेवानिवृत्त), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5750 दिनांक-09.04.13 एवं संकल्प ज्ञापांक-7018 दिनांक-16.05.12 से अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध महामहिम राज्यपाल, बिहार को समर्पित ज्ञापन (Memorial) दिनांक- 29.06.2014 पर विचारोपरान्त पूर्व के निर्णय का पुनरीक्षण करने के संबंध में।
7. संलेख की कंडिका 5 की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग

(विशेष)

9. दिनांक-03.06.2011 को फारबिसगंज जिला-अररिया में हुई पुलिस गोलीकांड की न्यायिक जाँच हेतु गठित आयोग का दिनांक-01.10.2014 से 28.02.2015 तक अवधि विस्तार के संबंध में।
9. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

10. बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ग' (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 के अनुमोदन के संबंध में।
10. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

11. बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ख' (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 के अनुमोदन के संबंध में।
11. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

12. बिहार राज्य अभिलेखागार रेप्रोग्राफिस्ट (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 के अनुमोदन के संबंध में। 12. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13. ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना को वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजनान्तर्गत रू० 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। 13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैरयोजनान्तर्गत सी०डब्लू० जे०सी० संख्या-5992/12 ललन दूबे एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के अनुपालन में भोजपुरी अकादमी, पटना के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को बकाये वेतनादि भुगतान हेतु रूपये 1,10,89,000/- (एक करोड़ दस लाख नवासी हजार रूपये मात्र) पुनर्विनियोग से सहायक अनुदान की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

15. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, छायाकार (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 के प्रस्ताव की स्वीकृति। 15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ अंचल के मौजा-वियावानी, थाना नं०-131, खाता नं०-201, खेसरा नं०-2066, रकबा-0.50 एकड़ (पचास डिसमिल) गैरमजरूआ आम किस्म 'पंचाने नदी' भूमि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 35,000/-रू० प्रति डिसमिल के दर से 17,50,000/- (सतरह लाख पचास हजार) रू० सलामी एवं सलामी का 2 प्रतिशत लगान अर्थात् 35,000/-रू० का 25 गुणा अर्थात् 8,75,000/-रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 26,25,000/- (छब्बीस लाख पचीस हजार) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 16. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. गया जिलान्तर्गत मानपुर अंचल के मौजा-भुसुण्डा, थाना सं०-317, खाता सं०-76, खेसरा नं०-590, रकबा-7.79 एकड़ गैर मजरूआ मालिक बालू भूमि का कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को मानपुर, गया में स्टेडियम निर्माण हेतु निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण। 17. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

18. वित्तीय वर्ष 2014-15 में उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार, पटना हेतु ₹ 71.00 लाख (एकहत्तर लाख) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।
18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले बिहार के नागरिकों के असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट उपबंधित राशि ₹ 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़) रुपये में से शेष बची राशि ₹ 16,67,00,000/- (सोलह करोड़ सड़सठ लाख) रुपये के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
19. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

20. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1595, दिनांक-22.09.2014 के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के अधीन गया जिले के खिजरसराय प्रखण्ड के अन्तर्गत महकार ग्राम में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार (गया) में सत्र 2014-15 में प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन हेतु आवश्यक संशोधन के संबंध में।
20. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

21. महादलित विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान वेतन मद में ₹ 80.00 लाख, सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण में ₹ 7529.23 लाख एवं सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में ₹ 14000.00 लाख यानि कुल ₹ 21609.23 लाख (दो सौ सोलह करोड़ नौ लाख तेईस हजार) उपलब्ध कराते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन कराने एवं व्यय करने की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत कतिपय ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास संस्थान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, पाटलीपुत्र औद्योगिक प्रांगण, पटना तथा सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार), औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर के द्वारा संचालित करने के लिये उक्त संस्था को नामित करने का प्रस्ताव। साथ ही विकास मित्रों का मानदेय वर्तमान ₹ 5000/-प्रतिमाह से ₹ 6000/-प्रतिमाह बढ़ाये जाने, विकास मित्रों को CUG Mobile सेवा उपलब्ध कराने हेतु ₹ 200/-प्रतिमाह देने, एक मोबाईल सेट प्रत्येक विकास मित्र को खरीदने हेतु ₹ 2500/-अनुदान, विकास मित्र के आकस्मिक मृत्यु के मामले में 36 माह के मानदेय के बराबर अनुदान भुगतान किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

21. स्वीकृत।

कृषि विभाग

22. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रुपये (अठानवे करोड़ रुपये) के विरुद्ध तत्काल 8292.00 लाख रुपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रुपये) का कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति।

22. स्वीकृत।

कृषि विभाग

23. किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रुपये को पुनरीक्षित करते हुए कुल 683.392 करोड़ रुपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रुपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति।

23. स्वीकृत।

कृषि विभाग

24. बिहार में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु बिहार राज्य बीज प्रमाणक एजेन्सी, पटना एवं उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणक एजेन्सी, देहरादून के बीच एकरारनामा (Agreement) करने की स्वीकृति।

24. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी)

25. पुलिस तथा अन्य बलों की आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के तहत राज्य योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य भवनों के निर्माणार्थ नयी योजनाओं की लागत राशि ₹ 15671.873 लाख (एक सौ छप्पन करोड़ इकहत्तर लाख सतासी हजार तीन सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में।

25. स्वीकृत।